भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2589

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026/19 फाल्गुन,1947 (शक) को दिया जाना है।)

परिवारों की निवल वित्तीय बचत और देनदारियां

2589. श्री बापी हलदर:

एडवोकेट प्रिया सरोज:

श्री पुष्पेंद्र सरोज:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2014 से देश में निवल घरेलू वित्तीय बचत, देनदारियों और ऋण-आय अनुपात का का राज्य-वार, वर्ष-वार, लिंग-वार और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार विशेष रूप से एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय देनदारियों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) युवाओं और पहली बार ऋण लेने वालों सहित असुरक्षित ऋणों के जनसांख्यिकीय और आय-समूह वितरण का राज्य-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार विशेष रूप से एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डिजिटली ऋण देने वाले प्लेटफार्मों के तेजी से विस्तार से अत्यधिक ऋणग्रस्तता, बढ़ती चूक या वित्तीय संकट के जोखिमों का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त जोखिमों को कम करने और उत्तरदायी ऋण देने की पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई विनियामक, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता संबंधी उपाय शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एटा, कासगंज और जौनपुर जैसे अर्ध-शहरी जिलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) से प्राप्त निवल घरेलू वित्तीय बचत और देनदारियों के आंकड़े, तथा आरबीआई बुलेटिन के आधार पर जारी ऋण-से-आय अनुपात के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। राज्यवार, वर्षवार, लिंगवार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, विशेषकर एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों से संबंधित जिलावार ब्यौरा आरबीआई द्वारा अलग से नहीं रखा जाता है।

घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ और ऋण-से-आय अनुपात											
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
₹ लाख करोड़											
सकल घरेलू वित्तीय बचत	12.6	15	16.1	20.6	22.6	23.2	30.7	26.1	29.8	35.8	38.3
घरेलू वित्तीय देनदारियाँ	3.8	3.9	4.7	7.5	7.7	7.7	7.4	9	16	18.8	15.7
शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत	8.8	11.1	11.5	13.1	14.9	15.5	23.3	17.1	13.9	17	22.6
घरेलू ऋण @						69.9	77.7	86.2	102.2	121	136.6
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में											
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कुल घरेलू वित्तीय बचत	10.1	10.9	10.5	12	12	11.6	15.4	11.1	11.4	12.3	12
घरेलू वित्तीय देनदारियां	3	2.8	3	4.4	4.1	3.9	3.7	3.8	6.1	6.5	4.9
निवल घरेलू वित्तीय बचत	7.1	8.1	7.4	7.6	7.9	7.7	11.7	7.3	5.3	5.9	7.1
घरेलू ऋण (जीएनडीआई के प्रतिशत के रूप में)						34.2	38.6	36.0	38.5	41.1	42.1

@ घरेलू ऋण के आंकड़े आरबीआई बुलेटिन तालिका 50 (ख) से लिए गए हैं, जो केवल 2019-20 से उपलब्ध है।

नोट: *सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल निवल प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) 2022-23 के आंकड़े 27 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए संशोधित आधार वर्ष के नवीनतम जीडीपी आंकड़ों पर आधारित हैं।*

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और आरबीआई।

(ख) घरेलू वित्तीय देनदारियां 2019-20 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में मध्यम और स्थिर रहीं, लेकिन महामारी के दौरान और उसके बाद इनमें तीव्र वृद्धि हुई, जो वर्ष 2023-24 में शीर्ष पर पहुंच गई, जो ऋण पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। दिसंबर 2023 में प्रकाशित आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार में भारी वृद्धि के कारण हुई, जिसका एक बड़ा हिस्सा भौतिक आस्तियों (मॉर्टगेजेज और वाहन) के निर्माण में परिणत हुआ। वर्ष 2024-25 में, कुल देनदारी और जीडीपी में हिस्सेदारी दोनों में गिरावट आई है, जो ऋण में कमी के शुरुआती संकेत देती है।

(ग) उत्तर प्रदेश (एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों सहित) के लिए असुरक्षित ऋणों के जनसांख्यिकीय और आय-समूह वितरण का राज्यवार, विशेषकर जिलावार विवरण, जिसमें युवा और पहली बार ऋण लेने वाले तथा क्षेत्रीय पैटर्न शामिल हैं, आरबीआई द्वारा अलग से नहीं रखा जाता है।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2025 के अनुसार, सीआरआईएफ हाई मार्क (आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्रेडिट सूचना ब्यूरो) द्वारा डिजिटल ऋण को अपने मुख्य रणनीतिक फोकस के रूप में रखने वाली राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत फिनटेक फर्मों द्वारा खुदरा ऋण सितंबर 2023 में कुल एनबीएफसी उपभोक्ता खंड ऋणों के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 8.9 प्रतिशत हो गया है। उनके ऋण पोर्टफोलियो का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा असुरक्षित ऋणों का है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु के उधारकर्ताओं को दिया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिनटेक फर्मों के पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत ऋणों का मूल्यह्रास (इंपेयरमेंट) पिछले वर्ष में कम हुआ है, जबकि ऋण में तेजी से विस्तार हुआ है। हालांकि, अन्य एनबीएफसी की तुलना में, छोटे ऋणों (₹50,000 तक) में मूल्यह्रास (इंपेयरमेंट) अपेक्षाकृत अधिक बताया गया है।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता में ज़िम्मेदार उधार (क्रेडिट डिसिप्लिन) लेने और ऋण अनुशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल करता है। इनमें ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाली वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना; बैंकों द्वारा जिला स्तर पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) जो विभिन्न लक्षित समूहों के लिए शिविर आयोजित करते हैं; ऋण अनुशासन और ज़िम्मेदार उधार लेने जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए वित्तीय जागरूकता संदेशों (एफएएमई) का प्रसार; और जनता के बीच वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा आयोजित वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) शामिल हैं।

एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में अब तक 11 वित्तीय साक्षरता केंद्र सीएफएल (सीएफएल) स्थापित किए जा चुके हैं, जो शिविरों के माध्यम से जिम्मेदार ऋण (क्रेडिट डिसिप्लिन) लेने के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर, 2025 तक इन जिलों में पांच एफएलसी (एफएलसी) स्थापित किए गए हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इन एफएलसी के माध्यम से आम जनता के साथ-साथ किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के लिए शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।